

nt>

Title: Regarding situation arising out of move to close more than 600 industrial units in Delhi.

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री जी ने बजट भाग में कहा कि 100 दिनों के अंदर लोगों को रोज़गार प्रदान करेंगे। लेकिन दिल्ली की वर्तमान सरकार अनेक लोगों को औद्योगिक ईकाइयों से विस्थापित कर रही है। इस कारण 63 हजार लोगों के सामने रोज़ी-रोटी का समस्या खड़ी हो गई है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने कहा है कि हम रोज़गार के अवसर सृजित करेंगे लेकिन दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार रोज़गार छीनने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ा और गम्भीर संकट है जिसके कारण लोगों की रोज़ी-रोटी का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री अवतार सिंह मडाना (फरीदाबाद) : अध्यक्ष जी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी औद्योगिक ईकाइयों को वहां से हटाया जाये।